भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

26.07.2023 के

अतारांकित प्रश्न सं. 1101 का उत्तर

ओडिशा में जारी रेलवे परियोजना

1101. श्री रमेश चन्द्र माझी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में विशेषकर नबरंगपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और मल्कानगिरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित ओडिशा में जारी रेलवे परियोजनाओं का परियोजना/क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्तमान वर्ष के दौरान नबरंगपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और मल्कानगिरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित ओडिशा में नई लाइनों/आमान परिवर्तन/दोहरीकरण परियोजनाओं के विकास के लिए निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) 2023-24 के दौरान बजट में ओडिशा में रेल परियोजनाओं के विकास के लिए आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) रेलवे द्वारा ओडिशा में इन लंबित रेलवे परियोजनाओं को गति देने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) उपरोक्त में से निर्धारित समय से पीछे चल रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(च) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

ओडिशा में जारी रेलवे परियोजना के संबंध में दिनांक 26.07.2023 को लोक सभा में श्री रमेश चन्द्र माझी के अतारांकित प्रश्न सं. 1101 के भाग (क) से (च) के उत्तर के संबंध में विवरण।

(क) से (च): रेल परियोजनाएं क्षेत्रीय रेलवे-वार स्वीकृत/कार्यान्वित की जाती हैं न कि राज्य-वार/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-वार/क्षेत्र-वार, क्योंकि रेल परियोजनाएं विभिन्न राज्यों की सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती हैं।

01.04.2023 की स्थिति के अनुसार, ओडिशा सहित भारतीय रेल पर, लगभग 7.18 लाख करोड़ रुपये लागत की 46,360 कि.मी. की कुल लंबाई की 459 रेल अवसंरचना परियोजनाएं (189 नई लाइनें, 39 आमान परिवर्तन और 231 दोहरीकरण) योजना/अनुमोदन/निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं, जिनमें से 11,872 कि.मी. लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च, 2023 तक लगभग 2.61 लाख करोड़ रु. का व्यय किया गया है।

ओडिशा :

01.04.2023 की स्थिति के अनुसार, नबरंगपुर एवं मलकानगिरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पूर्ण रूप से/आंशिक रूप से पड़ने वाली परियोजनाओं सहित ओडिशा राज्य में पूर्ण रूप से/आंशिक रूप से पड़ने वाली 52,189 करोड़ रुपये की लागत की 4,257 कि.मी. लंबाई की 35 परियोजनाएं (12 नई लाइन, 01 आमान परिवर्तन और 22 दोहरीकरण) योजना/अनुमोदन/निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं, जिनमें से 1,184 किमी. लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च, 2023 तक 20,141 करोड़ रु. का व्यय किया गया है।

ओडिशा में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाली रेल अवसंरचना परियोजनाएं भारतीय रेल के पूर्व तट रेलवे,दक्षिण पूर्व रेलवे एवं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आती हैं। रेल परियोजनाओं को लागत, व्यय और परिव्यय सहित उनका क्षेत्रीय रेल-वार ब्यौरा भारतीय रेल की वेबसाइट अर्थात् www.indianrailways.gov.in > Ministry of Railways > Railway Board > About Indian Railways > Railway Board Directorates > Finance (Budget)>Rail Budget/Pink Book (year)>Railways-wise Works, Machinery & Rolling Stock Programme पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है।

2014 के बाद से, परियोजनाओं के लिए बजट परिव्यय और तदनुरूपी कमिशनिंग में पर्याप्त वृद्धि हुई है। वर्ष 2014-19 के दौरान, ओडिशा राज्य में पूर्णत:/आंशिक रूप से पड़ने वाले अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए औसत वार्षिक बजट आबंटन को बढ़ाकर 4,126 करोड़ रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है, जो वर्ष 2009-14 के दौरान औसत वार्षिक बजट परिव्यय 838 करोड़ रुपये प्रति वर्ष से 392% से अधिक है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आवंटन को बढ़ाकर 4,568 करोड़ रुपये (2009-14 के औसत वार्षिक बजट आवंटन से 445% अधिक), वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 5,296 करोड़ (2009-14 के औसत वार्षिक बजट आवंटन से 532% अधिक), वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 6471 करोड़ रुपये (2009-14 के औसत वार्षिक बजट आवंटन से 672% अधिक) और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 9734 करोड़ रू. (जो 2009-14 के औसत वार्षिक बजट आवंटन से 1062% अधिक है) कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, इन परियोजनाओं के लिए 10,012 करोड़ रुपये का अभी तक का सबसे अधिक बजट परिव्यय मुहैया कराया गया है, जो 2009-14 के औसत वार्षिक बजट आवंटन से (838 करोड़/वर्ष) 1095% अधिक है।

रेल परियोजना(ओं) का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा त्वरित भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा वन संबंधी क्लीयरेंस, लागत साझा परियोजनाओं में राज्य सरकार द्वारा साझा लागत को जमा कराना, बाधक जनोपयोगी सेवाओं को हटाना, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक क्लीयरेंस, क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक स्थिति, परियोजना(ओं) स्थल के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु स्थिति को ध्यान में रखते हुए परियोजना विशेष को स्थल के लिए वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है और ये सभी कारक परियोजना(ओं) के समापन समय को प्रभावित करते हैं, जिन पर अंतिम चरण में विचार किया जाता है।

रेल परियोजनाओं के प्रभावी और त्वरित कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे विभिन्न उपायों में (i) गति शक्ति इकाइयों की स्थापना (ii) परियोजनाओं की प्राथमिकता तय करना (iii) प्राथमिक परियोजनाओं में निधि के आवंटन में पर्याप्त वृद्धि (iv) फील्ड स्तर पर शक्तियों का प्रत्यायोजन (v) विभिन्न स्तरों पर परियोजनाओं की प्रगति की गहन निगरानी, और (vi) शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वानिकी और वन्यजीव संबंधी क्लीयरेंस और परियोजनाओं से संबंधित अन्य मुद्दों के समाधान के लिए राज्य सरकारों और

संबंधित प्राधिकरणों के साथ नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई करना शामिल है। इसके परिणाम स्वरुप 2014 से कमीशनिंग की दर में काफी वृद्धि हुई है।

वर्ष 2014-23 के दौरान, ओडिशा राज्य में पूर्णत:/आंशिक रूप से पड़ने वाले 1583 किमी खंड (384 किमी नई लाइन और 1,199 किमी दोहरीकरण परियोजनाएं) 175.89 किमी प्रति वर्ष की औसत दर से चालू किए गए हैं, जो 2009-14 के दौरान किए गए कमीशनिंग (53.4 किमी/वर्ष) से 229% अधिक है।

*****